www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 12 जून 2019

दैनिक जागरण

जोखिम उठाए बिना सफलता संभव नहीं

हर घर को नल से जल

मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में सभी को पेयजल उपलब्ध कराने को जिस तरह प्राथमिकता प्रदान कर रही है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हर घर को नल से जल पहुंचाने की योजना को वैसा ही महत्व मिलने वाला है जैसा पिछले कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान को मिला। हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना को तेजी से आगे बढ़ाना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि आज देश के 18 फीसद गांवों में ही नल से जलापूर्ति होती है। तथ्य यह भी है कि जहां अभी नल से जल की आपूर्ति होती है वहां या तो पेयजल की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है या फिर उसकी आपूर्ति बाधित हो रही है। एक संकट यह भी है कि देश के विभिन्न हिस्सों में भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है या फिर दूषित हो रहा है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक ओर जहां तमाम छोटी नदियां प्रदूषण अथवा अतिक्रमण के कारण नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई हैं वहां दूसरी ओर जल के अन्य परंपरागत स्रोत खत्म हो रहे हैं। इस सबको देखते हुए नवगठित केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को इसका अहसास होना चाहिए कि उसके सामने गंभीर चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना अकेले केंद्र सरकार नहीं कर सकती। जरूरी केवल यह नहीं है कि हर किस्म के जल संकट का समाधान करने में केंद्र को राज्यों का सहयोग मिले, बल्कि यह भी है कि पानी के सवाल पर किसी तरह की संकीर्ण राजनीति का परिचय न दिया जाए, क्योंकि आज वे राज्य भी जल संकट के मुहाने पर दिख रहे हैं जहां कई छोटी-बड़ी नदियां हैं।

यह सही है कि मोदी सरकार ने पिछले पांच साल में गंगा को साफ-सुथरा करने के लिए जो कोशिश की वह अब रंग ला रही है, लेकिन अन्य बड़ी नदियों के संरक्षण की योजनाएं कारगर होती नहीं दिख रही हैं। छोटी और मौसमी नदियों की तो कोई सुध लेने वाला ही नहीं दिखता। यह स्वागतयोग्य है कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यों के पेयजल मंत्रियों के साथ बैठक के बाद यह रेखांकित किया कि देश के 82 फीसद ग्रामीण हिस्से में पेयजल की आपूर्ति नल से करने का लक्ष्य तय कर लिया गया है, लेकिन यह एक कठिन लक्ष्य है। इसे इससे समझा जा सकता है कि आज केवल सिक्किम ही एक ऐसा राज्य है जहां 99 फीसद घरों में नल से जल पहुंचाया जाता है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राज्यों ने पानी के तर्कसंगत उपयोग पर सहमति जताई, क्योंकि इस तरह की सहमतियां अक्सर कागजी ही साबित होती हैं। बेहतर हो कि हर घर को नल से जल पहुंचाने की योजना को गति देने के साथ ही जल संरक्षण के उपायों पर सख्ती से अमल किया जाए और साथ ही पानी की बर्बादी रोकने के प्रभावी कदम उठाए जाएं। इसके लिए जरूरी हो तो नए कानूनों का निर्माण किया जाए। यह भी समय की मांग है कि नदी जल को संविधान की समवर्ती सूची में लाया जाए। निःसंदेह यह भी जरूरी है कि आम आदमी भी जल संरक्षण की परवाह करे।

सिंगुर में हार पर शर्म

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस सिंगुर को लेकर आंदोलन किया और जिसके बूते पर वह बंगाल की सत्ता तक पहुंचीं। उसी सिंगुर में 12 वर्ष बाद ऐसी हालत होगी शायद ही तृणमूल प्रमुख ने सोचा होगा। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर जिलावार समीक्षा में जुटीं ममता ने हुगली के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी। हुगली जिले की दो लोकसभा सीटें श्रीरामपुर एवं आरामबाग में तृणमूल को जरूर जीत मिली। लेकिन सिंगुर विधानसभा क्षेत्र वाले हुगली लोकसभा सीट भाजपा ने तृणमूल से छीन ली। यहां तक कि सिंगुर विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा को तृणमूल से अधिक वोट मिले। इस बात को ममता पचा नहीं पा रही हैं कि इतना काम करने के बावजूद लोग तृणमूल से दूर क्यों होते जा रहे हैं? यह बड़ा सवाल है जिस पर ममता को गंभीरता से विचार करना होगा। क्योंकि सिंगुर और नंदीग्राम दो ऐसे इलाके हैं जो तृणमूल और खासकर ममता बनर्जी के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। इन्हीं दो क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आवाज उठाते हुए धरना प्रदर्शन कर 34 वर्षों के वाम शासन का अंत किया था। यह क्षेत्र 2006-07 से पहले तक वाममोर्चा का गढ़ था और जो जमीन अधिग्रहण को लेकर तृणमूल का गढ़ बन गया था। यहां तक कि सिंगुर की लड़ाई लड़ कर ममता ने अनिच्छुक किसानों को जमीन भी लौटा दी, परंतु आज वही किसान खुश नहीं हैं। वे लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें तो जमीन मिल गई, लेकिन उसमें अब खेती करना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं कारखाने भी नहीं लगे। इस बात को अब ममता बनर्जी को समझना होगा। क्योंकि किसी को सरकारी मदद देकर अधिक दिनों तक वोट बैंक नहीं बनाए रखा जा सकता है। इसके लिए जरूरी पूरे इलाके का विकास है। ममता ने सिंगुर में पार्टी के प्रदर्शन पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा-'वहां काम करने के बावजूद हम खुद को सही तरीके से लोगों के बीच नहीं रख पाए, जिसका नतीजा रहा कि हमें वहां हार का सामना करना पड़ा, जो हमारे लिए शर्मनाक है।' उन्होंने आगे कहा कि पार्टी जनसंपर्क अभियान के जरिये राज्यभर के लोगों से संपर्क स्थापित करेगी। परंतु क्या सिर्फ जनसंपर्क अभियान से सबकुछ दुरुस्त हो जाएगा? जब तक लोगों ने जिस उम्मीद के साथ परिवर्तन किया था वह पूरा होता नहीं दिखेगा वे नहीं जुड़ेंगे। यह बात सभी दलों पर लागू होती है।

जयशंकर के कूटनीतिक कौशल की परीक्षा

विवेक काटजू

प्रधानमंत्री मोदी ने जयशंकर की क्षमताओं में जो विश्वास दिखाया है वही विदेश मंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी थाती है

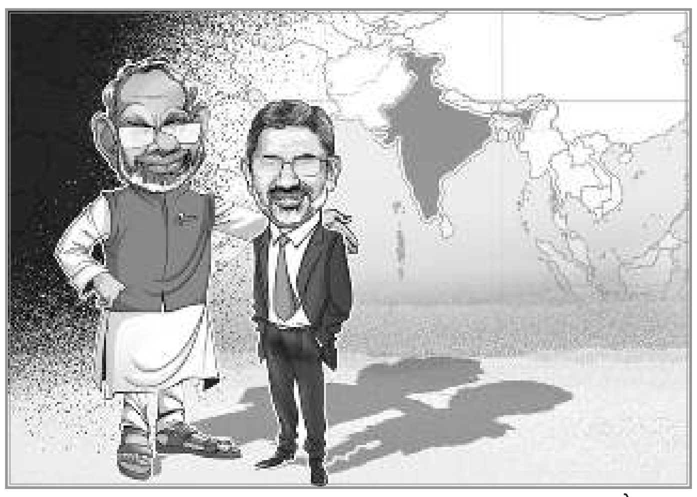

अवधेश राजपूत

इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं कि भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी सुब्रहमण्यम जयशंकर को विदेश मंत्री बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीतिक बिरादरी के साथ-साथ विदेश नीति और सुरक्षा वर्ग से जुड़े लोगों को चौंकाने का काम किया। इससे पहले जनवरी 2015 में भी उन्होंने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए तत्कालीन विदेश सचिव सुजाता सिंह को हटाकर जयशंकर को विदेश सचिव बनाया था। तब जयशंकर अमेरिका में भारत के राजदूत थे और बस सेवानिवृत्त होने वाले ही थे। स्पष्ट है कि भारत के कूटनीतिक रिश्तों को संभालने में मोदी को जयशंकर की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। मोदी को विश्वास है कि एक नेता के रूप में भी जयशंकर अपनी छाप छोड़ने में सफल होंगे। यहां यह उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्री के रूप में वह शीर्ष राजनीतिक पदों में से एक पर काबिज हुए हैं। वह सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस के भी सदस्य होंगे। इस समिति में सरकार के सबसे कद्दावर नेता शामिल हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह इसका हिस्सा हैं। इनके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इसमें शामिल हैं।

राजनयिक के रूप में जयशंकर का करियर बेहद शानदार रहा। उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक संभालीं। वह एक कुशल वार्ताकार के रूप में स्थापित हुए। उन्होंने भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों और विभिन्न क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर उठाए गए कदमों की हमेशा उपयुक्त व्याख्या की। अमेरिका और चीन जैसे दो देशों के साथ बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रिश्तों के मोर्चे पर उन्होंने अच्छा-खासा अनुभव अर्जित किया है। वाशिंगटन स्थित दूतावास की कमान संभालने से लेकर जयशंकर ने अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को कई अलग-अलग पहलुओं के लिहाज से साधने का काम किया है। इससे उन्हें यह समझने का अवसर मिला कि अमेरिकी तंत्र कैसे काम करता है। भारत-अमेरिका परमाणु करार को अंतिम रूप देने में भी उनका अहम योगदान रहा। इससे भारत-अमेरिका संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचे। अब विदेश मंत्री के रूप उन्हें अपना पूरा कौशल और अनुभव झोंकना होगा ताकि राष्ट्रपति ट्रंप की व्यापार और आव्रजन नीतियां भारत को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। ट्रंप अड़े हैं कि भारत अपने महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए पुराने साझेदार रूस से पीछा छुड़ाए। जयशंकर को इस मुश्किल का हल निकालना होगा।

जयशंकर करीब साढ़े चार साल चीन में भी भारत के राजदूत रहे और इस दौरान उन्होंने चीन को लेकर अपनी समझ बढ़ाई। भारत-चीन संबंधों की गुत्थी बहुत जटिल है और इसे सुलझाना भारत की कूटनीति एवं सुरक्षा प्रतिष्ठान के लिए मुख्य चुनौती बनी हुई है। जहां एक के बाद एक भारतीय सरकारें चीन के साथ सहयोग का दायरा बढ़ाने की उत्सुक रहीं वहीं चीन स्वयं और अपने पिट्ठू पाकिस्तान के माध्यम से भारतीय हितों पर लगातार आघात करता रहा है। चीन की मंशा अब वैश्विक मंच पर बड़ी भूमिका निभाने की है। इसके तहत वह पहले एशिया में अपना दबदबा बनाना चाहता है। वह भारत के पड़ोस में वर्चस्व कायम करने में लगा है। दक्षिण एशिया में अपनी पैठ बढ़ाने में जुटे चीन का रास्ता भारत को रोकना होगा। मोदी चीन की चुनौती से भलीभांति परिचित हैं। वह डोकलाम में इस चुनौती का सामना भी कर चुके हैं। तब विदेश सचिव के रूप में जयशंकर ने मोदी को सही राह दिखाई थी। इस लिहाज से यह एकदम उपयुक्त रहा कि बतौर विदेश मंत्री जयशंकर ने अपना पहला विदेशी दौरा भूटान का किया। इससे भूटान आश्वस्त हुआ होगा कि भले ही चीन का दबाव बढ़े, लेकिन भारत हमेशा उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।

विदेश सेवा अधिकारी के रूप में जयशंकर के पास बहुत व्यापक अनुभव रहा है। उन्होंने श्रीलंका, सिंगापुर और यूरोपीय देशों में भी सेवाएं दी हैं। उन्होंने सोवियत दौर में मास्को में सेवाओं के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके अलावा उन्हें सुरक्षा मामलों की समझ अपने पिता के. सुब्रहमण्यम से विरासत में मिली जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, लेकिन वह सामरिक मामलों में भारत के शुरुआती और बेहतरीन विशेषज्ञों में से एक के रूप में स्थापित हो गए थे। यह पूरा अनुभव विदेश सचिव के रूप में जयशंकर के बहुत काम आया। वह तीन वर्षों से अधिक तक विदेश सचिव रहे।

मोदी ने जयशंकर में बहुत भरोसा जताया है। वह एक तरह से मोदी के विदेश नीति सलाहकार बन गए थे। विदेश मंत्रालय की परंपरा से उलट मोदी ने जयशंकर से हमेशा अपने साथ बने रहने के लिए कहा। तब भी जब कोई मामला अन्य सचिवों के कामकाज से जुड़ा रहा। इस लिहाज से अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में जयशंकर का कद कुछ बड़ा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मंत्री के रूप में जयशंकर विदेश नीति और कूटनीतिक मसलों पर मोदी के मुख्य सलाहकार बने रहेंगे। कूटनीति में उनका व्यापक अनुभव नई भूमिका में बहुत मददगार साबित होगा, खासकर तब जब बाहरी परिदृश्य बहुत जटिल होता जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते विरोधाभास को देखते हुए भारत को इसके कारण पड़ने वाले असर का समाधान निकालना होगा। साथ ही अपने वाणिज्यिक, आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक हितों को देखते हुए भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप के साथ अपने रिश्तों में निरंतर धार देनी होगी। भारत को अपने पड़ोस पर नजर रखने के साथ ही पश्चिम एशिया में अपने हितों को भी सुरक्षित रखना होगा जहां काफी उथल-पुथल मची हुई है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की कड़ी नीतियों से भारत प्रभावित हुआ है। जयशंकर के सामने एक बड़ी चुनौती पाकिस्तान के मोर्चे पर भी होगी जो बातचीत के लिए तो बेचैन दिखता है, लेकिन भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले आतंकी ढांचे पर लगाम लगाने के कोई संकेत नहीं दे रहा है। उम्मीद यही है कि भारत इस रुख पर कायम रहेगा कि आतंकवाद के साथ वार्ता संभव नहीं हो सकती।

विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर ने सुषमा स्वराज की जगह ली है जो भारत की सबसे अनुभवी और लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। सुषमा स्वराज ने मंत्रालय को मानवीय पुट दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि विदेश में किसी भी भारतीय की परेशानी प्राथमिकता के आधार पर हल की जाए। उन्होंने भारतीय विदेश नीति में निरंतर संतुलन बनाए रखा। विदेश नीति पर भारत की स्थिति को संसद में रखने के मामले में उनका कोई सानी नहीं था। जाहिर है कि जयशंकर को जल्द ही राजनीतिक चोला भी पहनना होगा, जो एक मंत्री के लिए जरूरी है। मोदी ने जयशंकर की क्षमताओं में जो विश्वास दिखाया है वही विदेश मंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी थाती है। उनके प्रदर्शन पर जनता की नजर रहेगी। क्या वह जनता के भरोसे पर खरे उतर पाएंगे? अगर अतीत के प्रदर्शन को पैमाना माना जाए तो यह कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से वह अपनी छाप छोड़ने में सफल होंगे।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा

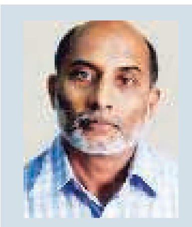

प्रेमपाल शर्मा

समर्थ वर्ग को मुफ्त यात्रा की सुविधा असमानता को बढ़ावा ही देगी। ऐसे वर्ग से तो ज्यादा किराया लिया जाना चाहिए

किसानों, मछुआरों, बुनकरों और गरीबों के लिए कुछ राहत या धन देने की बात तो एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारियों के तहत समझ आती है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार का यह प्रस्ताव समझ से परे है कि मेट्रो और डीटीसी की बसों में सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। पहले इस बात का जवाब तलाशते हैं कि किसानों के लिए ऐसी कोई राहत क्यों जरूरी है-चाहे वह पीएम-किसान के नाम पर हो या ओडिशा की कालिया योजना या तेलंगाना की रैयतबंधु योजना के नाम पर। चूंकि किसानों की कर्ज माफी या रियायती बिजली की लगातार आलोचना होती रहती है लिहाजा इसका जवाब सिर्फ यही है कि यदि किसान, मजदूर गांव छोड़कर शहरों, महानगरों में पहुंचने को विवश हो गया तो शहरी मध्य वर्ग की सारी सुविधाएं हवा हो जाएंगी। ध्यान रहे कि शहरों पर ग्रामीण आबादी के पलायन के चलते बहुत दबाव है।

ऐसे में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से जितनी भी रियायत दी जा सकें, दी जानी चाहिए। वास्तव में यदि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले और बिचौलिए उनका शोषण न कर सकें तो इस देश का किसान कभी भी खैरात की बदौलत जिंदा नहीं रहना चाहेगा। इस दूसरे विकल्प पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि किसानों को वाजिब दाम मिलेगा तो उनके साथ काम करने वाले मजदूरों को भी सही मजदूरी मिलनी संभव होगी। इससे एक स्वावलंबी कृषि व्यवस्था धीरे-धीरे पनपने लगेगी, लेकिन वोट की होड़ में दिल्ली की महिलाओं को मेट्रो और डीटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का विचार तो सरासर गलत है। इसमें यदि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाएं, बच्चियां शामिल हों तो एक बार को बात समझ में आती है, लेकिन सरकारी उपक्रमों, बैंकों, स्कूलों, कॉलेजों में कार्यरत और ठीक-ठाक वेतन/पेंशन पा रहीं महिलाओं को यह खैरात क्यों? समर्थ और संपन्न तबके से तो और अधिक किराया वसूला जाना चाहिए। समर्थ वर्ग को मुफ्त यात्रा जैसी सुविधा असमानता को और बढ़ावा ही देगी।

दिल्ली जैसे महानगर में मुफ्तखोरी के ऐसे और भी कई कार्यक्रम पिछले दो-तीन दशक से पनपे हैं। बतौर उदाहरण सौ-दो सौ घरों की कॉलोनी को अपने पार्क के रखरखाव के लिए हर साल एकाध लाख रुपये सरकार देती है। है न आश्चर्य की बात। वर्षों से यह चल रहा है। तथाकथित प्रबंधन समितियों के सदस्यों के चेहरे ऐसे पैसों से खिल उठते हैं। आश्चर्य की बात है कि इन कॉलोनियों में वह बुद्धिजीवी भी रहता है जो गरीबों के लिए सबसे अधिक आंसू बहाता है। सरकार को लूटने के लिए ऐसे कई मुखौटे इस शहर में ईजाद किए गए हैं। जाहिर है कि यदि आवासीय कॉलोनियों को पैसा दिया जा रहा है तो उन्हें कुछ सार्थक कामों जैसे कि भूमिगत जल संरक्षण और सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह काम एक नियमित कड़े निरीक्षण के तहत किया जाना चाहिए। दिल्ली की सत्ता में बैठे लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश की लगभग बीस प्रतिशत आबादी को आज भी केवल एक वक्त का खाना ही नसीब हो पाता है।

देश में गरीबी के ऐसे-ऐसे विवरण हैं जिन्हें सुनकर आत्मा कांप उठे। ओडिशा के उन लोगों को भूला नहीं जा सकता जो आम की गुठलियां खाकर जिंदा रहते हैं। वहां की एक 11 वर्षीय बच्ची का बयान था कि आर्थिक तंगी के कारण उसने कभी कोई सब्जी नहीं खाई। नमक-चावल या चावल के पानी से ही उसका जीवन चलता रहा है। दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाले कर्णधारों को यह समझना होगा कि महानगरों से बाहर भी देश है। यदि सरकारी खजाने में कुछ पैसा है तो अस्पताल बनवाओ, टूटे स्कूलों की मरम्मत करवाओ, उन सड़कों को ठीक करवाओ जिन पर चलना मुश्किल है। दिल्ली की बात करें तो यहां न तो गरीब बस्तियां कम हैं और न गरीब। दिल्ली में स्कूल-कॉलेजों की भी उतनी ही कमी है। इस सबको देखते हुए मेट्रो और डीटीसी की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का प्रस्ताव तो अनैतिक ही है।

यदि दिल्ली सरकार वाकई आधी आबादी यानी महिलाओं के प्रति संवेदनशील है तो उसे उनकी प्रमुख समस्या पर ध्यान देना चाहिए अर्थात उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि इस संबंध में निर्भया कांड से लेकर अब तक कई कानून बने हैं, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर माना जाता है। महिलाओं की इन चिंताओं को दूर करने के लिए पुलिस के समानांतर भी कोई व्यवस्था करनी पड़े तो राज्य सरकार को करनी चाहिए। हर सर्वे में दिल्ली महिलाओं की सुरक्षा के मामले में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के मुकाबले पीछे दिखती है। निःसंदेह दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से तीन गुनी और देश में सबसे अधिक है। इसके बढ़ते राजस्व का कारण अनेक प्रकार के भू-संपदा कर, राष्ट्रीय राजधानी को मिलने वाली रियायतें और बिक्री कर आदि हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को याद रखना चाहिए कि यह भारी-भरकम राजस्व ऐसे ही अनुत्पादक कार्यों पर उड़ाने के लिए नहीं है। यह सही है कि दुनिया के कुछ देशों ने इसी तरह के प्रयोग किए हैं, लेकिन इससे वहां कारों की खरीद पर कोई असर नहीं पड़ा। हम इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि भारत उन यूरोपीय देशों की तरह संपन्न देश नहीं है जहां महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के प्रयोग किए गए हैं।

एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में मेट्रो और डीटीसी की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने से सरकारी कोष पर सालाना करीब आठ सौ करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। क्या यह छोटी राशि है? इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि डीटीसी की बसों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। एक समय डीटीसी के बेड़े में छह हजार से अधिक बसें थी। आज उनकी संख्या चार हजार से भी कम रह गई है। एक तथ्य यह भी है कि दिल्ली सरकार ने पिछले चार साल से यानी 2015 से कोई बस नहीं खरीदी है। यह धारणा सही नहीं कि महिलाओं को मेट्रो और डीटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने से दिल्ली में कारों की खरीद में कमी आ जाएगी और उसके चलते प्रदूषण की रोकथाम होगी। ऐसा होने के कहीं कोई आसार नहीं, फिर भी ऐसे कथित सर्वेक्षण आ रहे हैं कि दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर अधिकांश लोग खुश हैं। इससे भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं।

(लेखक पूर्व प्रशासक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

परमात्मा

यह समस्त सृष्टि एक सुनिश्चित रचना है। इस रचना का एक-एक कण प्रभुसत्ता की नियमावली से अनुशासित है, नियंत्रित है। प्रभु सच्चिदानंद हैं। उनका मूल उद्देश्य प्राणिमात्र को शुभ आनंद प्रदान करना है। मनुष्य को छोड़कर विश्व का प्रत्येक प्राणी एक नैसर्गिक आनंद को प्राप्त करता है, परंतु मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो स्वतः आनंदित नहीं दिखाई देता। इसका स्पष्ट कारण यह है कि परमात्मा की इच्छा है कि वह उसके संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके आनंद की अनुभूति करे। वह भी, मात्र आनंद नहीं सच्चिदानंद परमात्मा की पूर्ण अनुभूति करे।

सत्, चित् अर्थात उसके अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करके आनंद की अनुभूति प्राप्त करे। उसे सच्चा आनंद तभी प्राप्त होगा, जब वह परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले। प्रभु ने अपनी इच्छा के अनुरूप मनुष्य को उपादान भी दिए हैं-अद्भुत शरीर, विलक्षण विवेक-बुद्धि। इनका उपयोग कर मनुष्य सहज ही परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अपनी विवेक शक्ति को विकृतियों से मुक्त कर मनुष्य यदि प्रत्यक्ष संसार को एक गहरी अनुभूति से देखे तो सहज ही वह परमात्मा के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है।

मनुष्य को आनंद की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, वह तो सच्चिदानंद परमात्मा से उत्पन्न इस आनंद क्या, सृष्टि में स्वयं ओतप्रोत है। मनुष्य को मात्र अपनी अनुभव शक्ति को प्रबुद्ध भर करना है। अनुभव शक्ति के प्रबोध हेतु उसे कोई विशेष तपस्या अथवा साधना नहीं करनी है। वह मात्र एक विस्मय मूलक दृष्टिकोण से उसकी रचना-संसार को देखे उसे श्रेष्ठ शिल्पकार की परमरचना समझकर सम्मान करे, इतना भर कर लेने से इसकी अनुभव शक्ति स्वतः प्रबुद्ध हो उठेगी और एक बार प्रबुद्ध हो जाने पर वह शक्ति पुनः निहित नहीं होगी। इतनी बड़ी रचना, इतनी महान कृति को उसने किस उद्देश्य, किस हेतु से किसके लिए निर्मित किया है? यह एक जटिल प्रश्न है, रहस्य है। मेरा तो मत है कि यह सब एक उस ही परमात्मा ने अपने से, अपने में, अपने लिए ही उत्पन्न किया है। सृष्टि में हर ओर से ओतप्रोत परमात्मा और परमात्मा में हर-प्रकार से समाहित यह संपूर्ण रचना, मनुष्य के समझने के लिए है। समझकर उस रचयिता का ज्ञान प्राप्त कर आनंद प्राप्ति के लिए है।

डॉ. विजय प्रकाश त्रिपाठी

जंगलों को आग से बचाने की चुनौती

चंदन कुमार चौधरी

आग लगने से एक तरफ वन संपदा का नुकसान तो होता ही है दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है

वन विभाग द्वारा तीन जून, 2019 को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में इस साल अभी तक 2,521 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुके हैं। इस आग से उत्तराखंड राज्य का पूरा वन क्षेत्र झुलस रहा है और कोई ऐसा जिला नहीं है जो इस भीषण आग की चपेट से अछूता हो। इस भीषण आग से घर और मवेशी भी सुरक्षित नहीं बचे हैं। वे भी इसमें स्वाहा हो रहे हैं। आग लगने के कारण क्षेत्र में इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और प्राकृतिक संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचा है।

ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर हम ऐसी स्थिति-परिस्थिति से कब तक जूझते रहेंगे। यह अकेले उत्तराखंड की स्थिति नहीं है, बल्कि इससे देश के अन्य क्षेत्रों में स्थित वन और अन्य क्षेत्र भी अक्सर प्रभावित होते रहते हैं। गर्मी के दिनों में इस तरह की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलती है और जब यह आग खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है तब इसकी रिपोर्ट होती है और लोगों को इसकी भयावहता के बारे में पता चलता है।

जंगलों में आग लगने की समस्या सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है। इसकी समस्या दुनिया के अन्य देशों में भी है। पिछले साल नवंबर में अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में लगी अब तक की सबसे भीषण आग में कई लोग मारे गए थे। आग के कारण कई हजार इमारतें तबाह हो गई थीं।

ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के जंगलों में पहली बार आग लगी है, बल्कि 2000 में जब से राज्य का गठन हुआ है तब से 44,518 हेक्टेयर जंगल आग में झुलस चुके है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हम इस दावानल से कब तक जूझते रहेंगे। आखिर ऐसा कोई ठोस कदम या उपाय क्यों नहीं किया जाता है जिससे इसका कोई स्थायी समाधान निकल सके। हमारे पास उन्नत संसाधन हैं और विज्ञान भी काफी तरक्की कर गया है। ऐसे में जंगलों और पेड़-पौधों को समझने और उसके हिसाब से रणनीति बना कर इस दिशा में अगर हम काम करें तो वह दिन दूर नहीं जब हम इस पर काबू पा लेंगे।

हमें समझना होगा कि जंगल में लगी आग से सिर्फ हमारे लाखों-करोड़ों रुपये की वन संपदा का ही नाश नहीं होता है, बल्कि इससे काफी चीज प्रभावित होती हैं। आग लगने से एक तरफ पेड़-पौधे का नुकसान तो होता ही है दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है। हमें फिर से नए-नए पेड़ लगाने पड़ते हैं और आग बुझाने के नाम पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। हमारे जंगलों में रहने वाले पशु-पक्षी भी इससे प्रभावित होते हैं और वनों पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों को भी इससे नुकसान झेलना पड़ता है। जंगल में लगी आग के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और इससे वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होती है।

ऐसे में हमें प्रकृति को सहेज कर रखना ही होगा। हमें समझना पड़ेगा कि इस मामले में उदासीनता आत्मघाती हो सकती है और दोषारोपण बेमानी। ऐसे मामले में केंद्र सरकार को इमर्जेंसी घोषित करके इसके स्थायी निवारण के लिए जिला प्रशासन, वन विभाग, राज्य सरकार और केंद्रीय समितियों एवं इससे संबद्ध मंत्रालयों को समयबद्ध कार्रवाई की जिम्मेदारी देनी चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

हिंदी का विरोध अनुचित

हिंदी विरोध की खोखली राजनीति शीर्षक से लिखे अपने लेख में हृदयनारायण दीक्षित ने राजभाषा हिंदी का महत्व बताया है। हिंदी की अनिवार्यता पर कुछ राज्यों ने जब विरोध किया तब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस पर जो यह कहा था कि किसी प्रदेश पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, यह उचित नहीं है, क्योंकि हिंदी 'कोई' भाषा नहीं, बल्कि हमारे देश की राजभाषा और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में एक मुख्य चिन्ह है। मोदी सरकार ने दूसरी बार फिर से सत्ता में आते ही नई शिक्षा नीति में हिंदी की अनिवार्यता समाप्त करके अपनी राजभाषा हिंदी के प्रति बेरुखी साबित कर दी है। यह हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की राह में बाधा उत्पन्न करेगी। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम इसके साथ इतनी भी अरुचि न दिखाए कि हिंदी अपने ही देश में बेगानी-सी लगने लगे। देश के इक्का-दुक्का राज्यों के विरोध के कारण सारे देश में ही नई शिक्षा नीति में हिंदी की अनिवार्यता समाप्त करना उचित नहीं है। मोदी सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। सवाल है कि सरकार अगर हिंदी की अनिवार्यता समाप्त कर रही है तो फिर देश की राष्ट्रभाषा किसे बनाएगी? पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी ने 1977 में अंतरराष्ट्रीय मंच पर हिंदी का मान बढ़ाया था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में जो भाषण दिया था, वह काफी लोकप्रिय हुआ था, क्योंकि यह पहला मौका था जब संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर हिंदी में किसी ने भाषण दिया था। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिन अंग्रेजों ने भारत को गुलाम करके भारतीयों पर तरह-तरह के जुल्म ढाए थे, आज आजाद भारत के वासी उनकी भाषा को पढ़ना-लिखना अपनी शान समझते हैं। ओछी राजनीति के कारण आज हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पा रही है, जबकि देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग हिंदी पढ़, लिख और समझ सकता है।

raju09023693142@gmail.com

प्रकृति को बचाएं तभी बचेंगे हम

इस बार भीषण गर्मी ने सभी को पानी की महत्ता का अहसास करा दिया। नदी, तालाब, कुएं, हैंडपंप आदि जलस्रोतों से मनुष्य, पशु-पक्षी, पेड़-पौधों आदि की जल संबंधी जरूरतें पूरी होती हैं। जल ही जीवन है और इसके अभाव में धरती पर जीवन की कल्पना नामुमकिन है। इस गर्मी में जलस्रोतों के न्यूनतम स्तर ने सभी के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। तपती गर्मी के थपेड़े मानव को वर्तमान में भविष्य के लिए जल संरक्षण के लिए जगा रहे हैं। यदि अब नहीं जागे, तो और भी भयावह स्थिति हो सकती है। गर्मी के प्रकोप ने देशभर में कितने ही जीव-जंतुओं की जानें लील लीं? जल की एक-एक बूंद अनमोल है। अब देश के विभिन्न इलाकों में मानसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। आगामी मानसून में सभी को दिल-दिमाग और तकनीक का उपयोग करके पानी को सहेजने का अपने-अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। मानसून पूर्व ही वाटर हार्वेस्टिंग के पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए। यह समय पुरानी बावड़ी, तालाब आदि के जीर्णोद्धार का है। पौधरोपण करके तापमान नियंत्रित करने, मृदा-जल के संरक्षण करने का है। यदि आज जागे, तो ये कदम हमारा भविष्य बचा लेगा। जल प्रकृति की अनमोल धरोहर है। इसके बावजूद, हम इसका अनावश्यक अति उपयोग या अपव्यय करते हैं, जिससे पारिस्थिकी तंत्र और मौसम चक्र की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौसम में हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि बरसात में लगाए पौधे जल्दी बढ़ते हैं। इन्हें पानी आदि ज्यादा देने की जरूरत नहीं होती है। प्रकृति को बचाएंगे तभी हम बचेंगे।

sonimohit895@gmail.com

प्राणीमात्र के अधिकार

मानवाधिकारों की बात तो ठीक है, पर हम यह विस्मरण कर रहे हैं कि यह संसार मात्र मानव के लिए नहीं है। यहां आनंदपूर्वक जीवन बिताने का अधिकार पशु एवं पक्षियों को भी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मई के अंतिम सप्ताह में एक मुकदमे में फैसला देते हुए पशुओं के अधिकारों के विषय में अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अत्यधिक ठंडक एवं गर्मी में पशुओं से कार्य नहीं लिया जा सकता है। इसी तरह दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में पक्षियों को पिंजरे में कैद करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट का कहना है कि पक्षियों को उन्मुक्त आकाश में उड़ने का नैसर्गिक अधिकार है और मानव उसको नहीं छीन सकता है। कोर्ट के ये दोनों निर्णय स्वागत योग्य हैं।

dharmendranath.rastogi@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।